WESTERN RAILWAY

P.S.No. 56/2013

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E/DAR/308/0 Vol.XI

Date: 31.7.2013

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Action to be taken in cases where the Railway Servants are convicted by criminal courts.

==========

A copy of Railway Board's letter No.E(D&A)2013 RG6-1 dated 8.7.2013 (RBE No.65/2013) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(G.S.Yadav)
Dy.CPO(HQ)
For General Manager (E)

RBE No. 65 /2013

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A) 2013 RG6-1

New Delhi, dated 8 .ग.2013

The General Managers (P),
All Indian Railways and
Production Units etc.,
(As per standard list).

Sub:- Action to be taken in cases where the Railway Servants are convicted by criminal courts.

A Zonal Railway had in the year 2011, referred to the Ministry of Railways for appropriate action, the case of a Railway servant who had retired from service on superannuation in January, 1992 and had been convicted by the CBI court on a criminal charge in November, 1992. The trial court had sentenced the retired Railway Servant concerned to undergo rigorous imprisonment of one year and to also pay a fine of ₹1000. The retired Railway servant concerned filed an appeal against his conviction which was admitted in December, 1992. While admitting the appeal the appellate court had granted bail to the convicted Railway servant and also stayed the realisation of fine from him pending disposal of his appeal.

2. The matter was examined by the concerned Directorate in this office and papers thereafter, were submitted to the Hon'ble Minister for Railways for consideration on behalf of the President under Rule 9 of Railway Services (Pension) Rules, 1993. Hon'ble Minister for Railways has taken a very serious view of the abnormal delay of as much as about two decades that has taken place in referring this case to the Board's office for further action.

3. The case records has revealed that the abnormal delay as aforesaid took place in the case mainly due to lack of clarity on the part of Zonal Railway authorities as to whether action could be taken against a Railway servant based on his conviction when the appeal filed by him against his conviction is pending. In this connection, attention of the Railways is invited to instructions contained in Board's letter No. E(D&A) 93 RG6-65 dated 6.6.1994. It may be noticed that these instructions clearly answers the issue in question. It has been categorically provided in Board's letter dated 6.6.1994 mentioned above that the mere filing of an appeal and/or stay of the execution of the sentence do not take away the effect of conviction, unless the appeal is allowed and the conviction is set aside by the appellate court. The competent disciplinary authority may proceed with the institution/completion of disciplinary proceedings, including imposition of the penalty as prescribed in the disciplinary rules, on the basis of conviction imposed on the Railway servant by a criminal court notwithstanding the fact that a higher court on an appeal filed by the railway servant concerned may order suspension of the "sentence" passed by the trial court till the final disposal of the appeal.

4. The instructions brought out in para 3 above are hereby reiterated for the information and guidance of all concerned. It may please be ensured that in case of conviction of a Railway servant on a criminal charge prompt action is taken in the light of

the position stated in Railway Board's letter dated 6.6.1994 under reference so that the type of the situation as took place in the case referred to in this letter, be avoided in future.

5. Please acknowledge receipt.

(Harish Chander)
Deputy Director Establishment (D&A)
Railway Board

आरबीई सं. 65/2013

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डीएंडए)2013 आरजी6-1 नई दिल्ली, दिनांक 8.07.2013

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां आदि,
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: फौजदारी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए रेल कर्मचारियों के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई।

एक क्षेत्रीय रेलवे ने जनवरी, 1992 में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हुए एक रेल कर्मचारी, जिसे नवम्बर, 1992 में सीबीआई अदालत द्वारा आपराधिक आरोप के संबंध में दोषी ठहराया गया था, का मामला वर्ष 2011 में रेल मंत्रालय को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा था। ट्रायल कोर्ट ने संबंधित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई थी। संबंधित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी ने इस सजा के खिलाफ अपील दायर की थी जिसे दिसम्बर, 1992 में एडमिट किया गया था। अपील एडमिट करते समय अपीलीय अदालत ने अपील का निपटान होने तक दोषी ठहराए गए रेल कर्मचारी को जमानत प्रदान की थी और उससे जुर्माना लिए जाने पर भी स्थगन आदेश दे दिया था।

2. इस कार्यालय के संबंधित निदेशालय द्वारा इस मामले की जांच की गई और तत्पश्चात् दस्तावेजों को रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के तहत राष्ट्रपति जी की ओर से विचार करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी को प्रस्तुत किया गया। माननीय रेल मंत्री जी ने इस मामले को आगे की कार्रवाई करने के लिए बोर्ड कार्यालय को भिजवाने में लगी लगभग दो दशकों की असामान्य देरी को बहुत गंभीरता से लिया है।

3. इस मामले के दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि उपर्युक्त असामान्य देरी मुख्य रूप से इस कारण से हुई कि क्षेत्रीय रेलवे प्राधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं था कि क्या किसी ऐसे दोषी ठहराए गए रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जब उसे दोषी ठहराने के विरुद्ध उसके द्वारा दायर की गई अपील पर अभी निर्णय होना हो। इस संबंध में, रेलों का ध्यान बोर्ड के दिनांक 6.6.1994 के पत्र सं. ई(डी एंड ए) 93 आरजी6-63 में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि इन अनुदेशों से इस मुद्दे में निहित प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। ऊपर उल्लिखित बोर्ड के दिनांक 6.6.1994 के पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि मात्र अपील दायर करने और/अथवा सजा के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिए जाने से दोषी ठहराए जाने का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा अपील को मान नहीं लिया जाता अथवा दोषसिद्धि रद्द नहीं हो जाती। इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा दायर की गई अपील पर उच्चतर न्यायालय द्वारा अपील को अंतिम रूप से निपटाए जाने तथा ट्रायल कोर्ट द्वारा पास की गई "सजा" के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया हो तब भी सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी फौजदारी अदालत द्वारा रेलवे कर्मचारी की दोषसिद्धि के आधार पर अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार कार्रवाई करते, जिसमें अनुशासनिक कार्रवाई के उपरांत दंड लगाना शामिल है, की कार्रवाई कर सकती है।

E (D&A) Mangal SK

...2

4. एतद्द्वारा ऊपर पैरा 3 में दिए गए अनुदेश, सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए दोहराए जाते हैं। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि आपराधिक आरोप के संबंध में रेल कर्मचारी के दोषी पाए जाने के मामले में, रेलवे बोर्ड के दिनांक 6.6.1994 के संदर्भाधीन पत्र में दी गई स्थिति के अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि इस पत्र में उल्लिखित मामले में जैसा हुआ है इस प्रकार की स्थिति भविष्य में न हो।

5. कृपया पावती दें।

(हरीश चन्द्र)
उप निदेशक स्थापना (डी एंड ए)
रेलवे बोर्ड